Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 15, Issue No. 12, December-2018, ISSN 2230-7540

नक्सलवाद: एक अध्ययन

Sunita*

M.Phil., Net Qualified, Department of Political Science

सार - ***यू तो सामाजिक जीवन में हर इंसान सुकुनभरी जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन अंदाजा लगाईए कि उस व्यक्ति की जिंदगी में कितनी पीड़ा होगी जिसकी हर सुबह-शाम डर में पनपती हो और इतना ही नहीं अगर किसी व्यक्ति को बिना वजह अपनों को खोना पड़े। यह न केवल चिंता का विषय है बल्कि बैठकर मंथन करने वाली बात हैं कि हम कैसे समाज, कैसे परिवेश और कैसे वातावरण में जी रहे हैं जो इंसान को उसके जीवन की सुरक्षा भी नहीं दे सकता बाकी बातें तो अलग बात हैं।***

शब्द - नक्सलवाद, समस्या, समाधान, सरकार, सामाजिक आर्थिक, पुलिस प्रशासन, आदिवासी

----------x----------

भूमिका

नक्सलवाद देश की एक बड़ी समस्या हैं और बीते हुए कुछ सालों में इसने काफी उग्र रूप धारण कर लिया है। वर्तमान में नक्सलियों का प्रभाव पशुपति (नेपाल) से तिरूपति (आंध्रप्रदेश) तक हो चुका है। धन बल में ये काफी मजबूत हैं। नक्सली क्षेत्रों में आंबटित पैसा नेता अफसरों और ठेकेदारों के बीच बंट जाता है। बात यही खत्म नहीं होती और यही पैसा अंतत नक्सलियों तक पहुंच ही जाता है जिसका उपयोग वे हिंसात्मक गतिविधियों में करते हैं।

देश के लगभग 40 प्रतिशत भू-भाग (20 राज्यों के 223 जिलों) पर उनकी समानांतर सरकार चलती है। देशभर में इनकी संख्या 1 लाख से 2 लाख तक मानी जाती है। नक्सलवादी समस्या आज किसी अकेले राज्य की समस्या नहीं बल्कि यह कई राज्यों की साझा समस्या है। जिसमें छतीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, बिहार, आंध्रप्रदेश, झारखंड आदि प्रमुख राज्य हैं जो इनकी आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित कर रही हैं। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि इसे वर्तमान में एक अहम समस्या के रूप में देखा जाए और नासुर बन चुके इस रोग का नये सिरे से सभी राज्यों से बातचीत करके सामाधान निकाला जाए। आज के इसी भाग में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि नक्सलवाद हैं क्या और इससे निपटने की सरकार की क्या रणनीति हैं?

नक्सलवाद की जड़ें

भारत में नक्सली हिंसा की शुरूआत 1967 में पश्चिमी बंगाल के नक्सलबाड़ी से हुई थी। शुरू-शुरू में पुलिस ने इस विद्रोह को कुचलने की कोशिश की लेकिन दशकों बाद इसने कई राज्यों में अपना प्रभुत्व कायम कर लिया जो आज की एक गंभीर समस्या हैं।

नक्सलवाद कम्युनिस्ट

क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम हैं जो भारतीय कम्यूनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है। नक्सल शब्द की उत्पति पश्चिमी बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई है जहां भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरूआत की। मजूमदार चीन के कम्यूनिस्ट नेता माओत्से तुंग के बहुत बड़े प्रंशसकों में से एक हैं। उनका मानना था कि भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से उच्च वर्गों का शासन तंत्र, कृषि तंत्र पर स्थापित हो गया हैं। इस अन्यायही दमनकारी वर्चस्व को केवल सशस्त्र क्रांति से ही समाप्त किया जा सकता है। 1967 में एक अखिल भारतीय समन्वय समिति नक्सलवादियों द्वारा बनाई गई। इन्होंने अपने आप को कम्यूनिस्ट पार्टी से अलग कर लिया और मजूमदार की मौत के बाद यह आन्दोलन अनेक शाखाओं में विभक्त हो गया और अपने लक्ष्य से भटक गया है तथा उग्र रूप

www.ignited.in

धारण कर लिया जिसका परिणाम आज देश के सैनिकों और वहां के आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा हैं। समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं निकला हैं लेकिन बीते तीन सालों में नक्सलवादी घटनाओं में कमी आई हैं और यह निरंतर घट रही है।

नक्सलवाद के कारण

आमतौर पर नक्सल प्रभावित जिलों को केन्द्र और राज्य सरकार द्वार इतना पैसा मुहैया करवाया जाता है अगर उस पूरे पैसे को सही तरीके से खर्च किया जाए तो जिले और राज्य की तस्वीर बदल सकती हैं। काश! ऐसा ही हो पाता। आपको यह जानकार हैरानी होगी कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की अधिकांश आबादी बिना बिजली और शौचालय के रहती हैं। अगर कोई बीमार हो जाए तो आस-पास अस्पताल तक नहीं और दूर-दराज के इलाकों में जाने की यातायात सुविधा नहीं और शहरी इलाज होते ही इतने महंगें हैं, कि आम नागरिक की पहुंच में ही नहीं हैं। इसका तात्कालिक कारण यह है कि न तो व्यवस्था सुधर रही है और न ही सुधरने का कोई संकेत हैं। यह आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा हैं। इसमें होने वाली राजनीति को देखकर सोचना पड़ता है वर्ग संघर्ष के पीछे राजनीति हैं या राजनीति के कारण वर्ग संघर्ष बढ़ रहा हैं।

किसानों की भूमि सुधार की मांगों को लेकर उठाने वाले इस आंदोलन का आरोप है कि भारत में भूमि सुधार की रफ्तार काफी धीमी हैं। उन्होंने आकंड़े देकर कहा है कि चीन में यह दर 4.5 प्रतिशत, जापान में 33 प्रतिशत लेकिन भारत में आजादी के बाद तो केवल 2 प्रतिशत जमीन का आवंटन हुआ है। नक्सलियो का विस्तार इसलिए हो रहा है क्योंकि आदिवासियो की समस्याओं को आज तक ठीक से समझा नहीं गया हैं। नक्सलियों के इतने शक्तिशाली होने के पीछे भी आदिवासियों का सहयोग ही है। चाहे नक्सली ऑपरेशन हो या नक्सल विरोधी ऑपरेशन इन दोनों के बीच अगर कोई सबसे ज्यादा पीड़ित है तो वह आदिवासी समुदाय है। इसका एक कारण यह भी है कि पुलिस नक्सलियों पर छोटी-मोटी बातों जैसे सुखी लकड़ी उठाना, चारे के लिए पत्तियाँ तोड़ना इत्यादि को लेकर मुकदमे दर्ज कर लेती हैं। इसी कारण एक लाख से अधिक मामले तो ऐसे ही लंबित पड़े हैं जिनका कोई ठोस आधार भी नहीं लेकिन फिर भी आदिवासी इनसे पीड़ित हो रहे हैं। यही वजह रही हैं कि आदिवासियों का पुलिस पर से विश्वास उठ गया हैं और वो वक्सलियों का साथ देने लग गए हैं।

आदिवासी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आवास की स्थिति दलितों से बदतर हैं। यह मानने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए कि आज तक आदिवासी हमेशा हाशिए पर ही रहे हैं।

नक्सलियों के पनपने का एक कारण प्रशासनिक भी हैं। स्पष्ट है कि हमारी न्यायपालिका में विवाद काफी लंबे चलते हैं और ये बहुत अधिक खर्चीले भी हैं। जिन आदिवासियों के पास मूलभूत सुविधाओं का अभाव हैं वो वकीलों का बोझ कैसे उठाएगें। लंबित मामले पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलते हैं जबकि नक्सली सरकारें समांतर चलती हैं। जो वहीं मेज कुर्सी लगाकर तुरंत फैसला करते हैं।

नक्सली समाज के ऐसे वर्ग के लोग है जिनकी बुनियादी जरूरतें एक सीमा तक ही हैं व्यवस्था चलाने वाले अधिकारी और सरकार भ्रष्टाचार के कारण इनकी आम जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर ये लोग हथियार उठाने लग गए। इन लोगों को जन्म देने का श्रेय नेता कानून मीडिया को जाता हैं। मीडिया वालों ने नेता और कानून के इस खेल में नक्सलियों के अधिकार की लड़ाई को अपराध की प्रवृत्ति बताकर हमेशा पैसों वालों का ही साथ दिया और इन आम लोगों को समाज और देश के दुश्मन बताकर नक्सलवादी नाम दे दिया।

सामाजिक आर्थिक कारण भी नक्सलवादी को पनपने में बराबर के हिस्सेदार रहे हैं। किसी भी समाज या व्यक्ति पर दो तरह से ही अधिकार किया जा सकता है एक शारीरिक व दूसरा मानसिक। शारीरिक रूप से अधिकार बंदूक और भय से तथा मानसिक रूप से अधिकार करने के लिए नैतिक साधनों का सहारा लिया जा सकता हैं जिसमें यह दिखाया जाता है कि वर्तमान शासन तंत्र तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा हैं। इसलिए हमें सहयोग दो। नक्सलवादियों की यही रणनीति रही हैं कि आदिवासी लोगों को सामाजिक तनाव देकर उन पर अपनी मानसिकता थोपी जाए जिसमें वे काफी हद तक सफल भी रहे हें। एक और कारण आदिवासियों की अज्ञानता और अशिक्षा हैं। जिसके कारण उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता। ये अपने रास्ते से भटक कर नक्सलियों का साथ देते हैं और फिर खुद भी इस चक्कर में फंस जाते हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

समय-समय पर सभी सरकारों ने इस समस्या पर ध्यान दिया हैं। सरकार को नक्सलवादी समस्या को हल करने में विश्वास बहाली, समझौता पर कार्य करना चाहिए ताकि नक्सलवादियों को सही दिशा मिल सकें। इसके लिए दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठकर बातचीत की पहलकदमी करनी चाहिए साथ ही पहले उन्हें हथियारों का समर्पण करने के लिए राजी करना चाहिए। इसके साथ ही राज्य में स्थित नक्सली और गैर-नक्सली की पहचान करना भी जरूरी हैं। सरकार सेना को नक्सली ऑपरेशनों में सीधे शामिल नहीं कर बल्कि परोक्ष तौर

पर उनकी मदद करें और नक्सल विरोधी टास्क फोर्स को प्रशिक्षण दें। सरकार ने संचार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए इन इलाकों में मोबाइल टॉवर बड़ी संख्या में लगाए हैं। साथ ही सरकार बुनियादी ढाँचे, कौशल विकास, शिक्षा, ऊर्जा और डिजिटल सहयोग का यथा संभव विस्तार करने के प्रयास कर रही हैं जिससे लोगों में जागरूकता फैलें और वे अपने फैसले उचित दिशा में बेहतर जीवन की तलाश में ले सकें। इसका ताजा उदाहरण छतीसगढ़ पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए नारायणपुर में एक स्कूल खोला गया हैं जिसमें तीन शिक्षक और 300 ऐसे नक्सली पढ़ रहे हैं जो अब पुलिस बल का हिस्सा हैं। जून 2013 में आजीविका योजना के तहत 'रोशनी' नामक विशेष पहल की भी शुरूआत की गई ताकि अधिक से अधिक नक्सलवाद प्रभावित युवाओं को रोजगार दिला सकें।

समाधान नामक 8 सूत्री पहल की भी घोषणा की गई हैं जिसमें नक्सलियों से लड़ने के लिए रणनीतियों और कार्य योजनाओं पर जोर दिया गया हैं। सरकार द्वारा कई अभियान भी चलाए गए जिसमें प्रहार, स्टीपचेलत्स, ग्रीनहंट अभियान शामिल हैं। जिसके कारण नक्सलवादी हिंसात्मक गतिविधियों में गिरावट देखी गई।

निष्कर्ष

उर्पयुक्त चर्चा के बाद यही कहा जा सकता है कि माओवादी हिंसा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राजनैनिक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में सुधार के साथ ही नियंत्रण की भी आवश्यकता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में आम लोगों की सुरक्षा के साथ ही शांतिपूर्ण योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। केन्द्र व राज्य सरकारों को मिलकर हिंसा प्रभावित क्षेत्रो में बुनियादी सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क रोजगार आदि उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि आदिवासी लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और उनमें जागरूकता लाई जा सकें। नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में टास्क फोर्स का गठन हों और पुलिस प्रशासन के प्रति लोगों विश्वास पैदा किया जा सकें। सबसे ज्यादा आवश्यकता ऐसे नेतृत्व की हैं जिसमें इस समस्या को समूल नष्ट करने की इच्छा शक्ति व विश्वास हो लेकिन बिडम्बना यह है कि भारत सरकार नक्सलवाद से निपटने के लिए न तो वैचारिक रूप से तैयार है और न ही खत्म करने की दृढ़ मानसिकता बना पा रही हैं। इसलिए सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए कारगर व उचित रणनीति बनाने की सख्त आवश्यकता हैं ताकि नक्सलवाद जैसी गंभीर समस्या का समाधान किया जा सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. https://www. hindivyakarn.com
2. www.essaysinhindi.com
3. Quiz Guru I as Academy.
4. https://hi.m. Wikipedia. org. नक्सलवाद
5. https novbharatimes. indiatimes.com
6. https://www. dristias.com. क्या हैं नक्सली समस्या का समाधान
7. www. Bhaskar.com आखिर क्या हैं नक्सलवाद और इसका मर्म
8. www. bbc. com. क्यों विकट होती जा रही हैं नक्सली समस्या

Corresponding Author

Sunita*

M.Phil., Net Qualified, Department of Political Science

sunitayadav10588@gmail.com